

आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़)
प्रादेशिक समाचार

1910 मंगलवार

26.08.2025

मुख्य समाचार:-

- 1— मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जापान प्रवास के दौरान विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ तीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2— केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के कार्यों की समीक्षा-छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी हुए शामिल।
- 3— छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन वाहनों को ढंककर किया जाए।
- 4— नगरीय प्रशासन विभाग ने रैलियों, आमसभाओं और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश।

मुख्यमंत्री-जापान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगी, बल्कि उच्च-तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगी। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि जापान यात्रा के दौरान विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ तीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान का दौरा करेंगे। श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ल्ड एक्सपो के जरिये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और औद्योगिक प्रगति को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री-स्वच्छ भारत मिशन

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने शहरी स्वच्छता के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्षित स्वच्छता इकाइयों के चिन्हांकन तथा 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था और स्वच्छता सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रही है।

श्री साव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर प्रदेश में भी राज्य स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा।

हाईकोर्ट—कोल/फलाई ऐश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोयला और फलाई ऐश का परिवहन वाहनों को ढंककर किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बगैर तारपोलिन से ढंके वाहनों को परिवहन की अनुमति नहीं दी जाए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम—एनटीपीसी और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड—एसईसीएल के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कोयला और फलाई ऐश के ट्रांसपोर्टर्स को संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट—सड़क रखरखाव

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की प्रमुख सड़कों की खराब स्थिति और उसके रखरखाव में बरती जा रही देरी तथा लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब चार सितंबर को होगी।

हाईकोर्ट—न्यायाधीश स्थानांतरण

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने देशभर के चौदह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय अग्रवाल का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा गया है।

ईएसआईसी—स्त्री योजना

केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक जुलाई से स्त्री योजना की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान इक्कीस दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम—ईएसआईसी योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत ईएसआईसी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग स्थित अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य लाखों असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआईसी दायरे में लाना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभों का लाभ मिल सके।

राज्यपाल—खैरागढ़

राज्यपाल रमेन डेका अपने खैरागढ़ प्रवास के दौरान चंदैली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, खाद्य सामग्री, परिधान और ग्रामीण उद्यमिता के मॉडल की प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्व-सहायता समूह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं और सरकार द्वारा इन समूहों को लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को कचरा संग्रहण के लिए गार्बेज रिकशा भी प्रदान किए गए।

खैरागढ़ प्रवास के दौरान राज्यपाल ने सोनपूरी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सोनपूरी को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पांच-पांच हजार रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की।

नगरीय प्रशासन विभाग-निर्देश

प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग ने रैलियों, आमसभाओं और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा, सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के निदेशक रेमेजियस एक्का ने बताया कि नगरीय निकायों में सड़कों, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थानों पर पडालों, अस्थायी संरचनाओं, धरना, आमसभा और रैली में एक समय में पांच हजार वर्ग फीट क्षेत्र में अधिकतम पांच सौ और उससे अधिक क्षेत्र में पांच सौ से अधिक लोगों के ठहरने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के रैलियां, आमसभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

श्री एक्का ने बताया कि आयोजकों को मानचित्र का लेआउट, आयोजन स्थल का विवरण, तिथि और अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

चैतन्य बघेल-याचिका

शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर पर चल रही जांच को रद्द करने की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने इसके लिए अनुमति दे दी है।

बारिश

बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कारण इंद्रावती सहित अन्य नदी-नाले उफान पर है। जिले के बीजापुर और भैरमगढ़ ब्लॉक में नदी पार करते समय दो ग्रामीण बह गए हैं। नगर सेना के जवान इन ग्रामीणों की तलाश में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नहीं जाने की अपील की है।

वहीं, दंतेवाड़ा में बारिश के कारण डंकिनी नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बालपेट के खालेपारा में नाले के तेज बहाव में फंसे तीस लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से उफान वाले नदी-नालों को पार न करने की सलाह दी है।

उधर, जांजगीर-चांपा में लीलागर नदी में बहे एक युवक का शव एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने छब्बीस घंटे बाद बरामद कर लिया है।

संक्षिप्त समाचार

- “हर घर मुनगा” अभियान के तहत रायपुर जिला प्रशासन और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और हितग्राही परिवारों को मुनगे के पौधे वितरित किए जा रहे हैं।
- पुलिस विभाग द्वारा साइबर ठगी की घटनाओं में जागरूकता लाने के लिए रायपुर से प्रदेश भ्रमण पर निकला साइबर सतर्क रथ जांजगीर पहुंचा। इस दौरान नुक्कड़-नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव के बारे में जागरूक किया गया।
- बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर फर्जी अंकसूची के आधार पर की गई भर्ती के मामले में पुलिस ने स्कूल संचालकों और फर्जी अंकसूची बनाने वालों को गिरफ्तार किया है।
- रायगढ़ जिले में लैलूंगा वन परिक्षेत्र में सत्ताईस हाथियों के दल ने तीन कच्चे मकानों को तोड़ दिया। वहीं, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया है।

